19042015-ls-ngp-04.qxd 04/19/2015 12:38 PM Page 1

और... एक शे'र

हद-ए-शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव-पांव चलीं,
सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छांव-छांव चली।
-अज्ञात

लोकमत समाचार

तमसो मा ज्योतिर्गमय

{ जिस राष्ट्र में चरित्रशीलता नहीं हो उसमें कोई योजना काम नहीं कर सकती. ■ विनोबा भावे }

संपादकीय

उद्योगों को निगरानी का भय भी हो

प्रदूषण एक गंभीर और बड़ा मुद्दा है, चाहे वह औद्योगिक प्रदूषण हो या अन्य कोई दूसरी तरह का. औद्योगिक प्रदूषण पर अनेक बार संसद में भी खूब चर्चाएं हुईं, राज्यों में तो होती ही रहती हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात का ही रहा. नदियों को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए इस पर भी अनेक समितियां काम कर चुकी हैं, फिर भी बात नहीं बनी. उद्योगों के खतरनाक अपशिष्ट को नदी-नालों में फेंकना अब तक रुका नहीं है. गंदे पानी को इधर-उधर छोड़ना भी बदस्तूर जारी है. लिहाजा, महाराष्ट्र में उद्योगों और औद्योगिक प्रदूषण पर ऑनलाइन निगरानी शुरू होने वाली है. यह नई व्यवस्था महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग ने की है. जाहिर सी बात है कि पहले की व्यवस्था कहीं न कहीं औद्योगिक प्रदूषण रोकने में नाकाफी साबित हुई. नई व्यवस्था के तहत अपशिष्ट के निपटान पर ऑनलाइन निगरानी होगी, इसके साथ ही जहरीले धुएं को पर्यावरण में फैलने से रोकने के लिए उद्योगों की चिमनियों में प्रदूषण नियंत्रक यंत्र लगाए जाएंगे. इन व्यवस्थाओं के जरिए यह पता लगाना अब आसान हो जाएगा कि कल-कारखानों में प्रदूषण नियामकों का कितना पालन किया जा रहा है. चिमनियों में यंत्र लगाकर धुएं के प्रदूषण को रोकना आसान हो सकता है, लेकिन अपशिष्ट के निपटान पर निगरानी किसी चुनौती से कम नहीं होगी. भले ही अब ऑनलाइन की व्यवस्था क्यों न हो, मामला बहुत पेचीदा है. औद्योगिक प्रदूषण एक गंभीर विषय होने के बावजूद अक्सर इसे बहुत हल्के से लिया गया. ठेके पर अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था कर कल-कारखाने अपनी जिम्मेदारी का इतिश्री समझ लेते हैं. अब अपशिष्ट उठाने वाला इसे नदी में फेंके या और कहीं, उद्योगों को इससे कोई लेना-देना नहीं. औरंगाबाद का ही एक उदाहरण सामने है जहां हाल ही में एक रैकेट पकड़ा गया जो कारखाने का अपशिष्ट नदियों में फेंका करता था. कारखानों का गंदा पानी अक्सर नदी-नालों में ही छोड़ा जाता है, कहीं-कहीं खुली जगहों पर भी. चूंकि उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती इसलिए यह आदत सी बन पड़ी है. इससे पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही. तकनीकी क्रांति के युग में उद्योगों पर बारीकी से नजर रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, फिर भी नियम-कायदे को ताक पर रखने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए बिना कोई भी व्यवस्था अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती. इस नई व्यवस्था से काम थोड़ा आसान जरूर हो जाएगा, लेकिन कार्रवाई कितनी सख्त होती है? यह एक बड़ा सवाल है. जब तक आसानी से लाइसेंस मिलता रहेगा तब तक शायद ही कोई उद्योग प्रदूषण मानकों पर खरा उतरने का ईमानदारी से प्रयास करे. दरअसल कानून का कोई भय नहीं रह गया है. मामूली कार्रवाई या दंड उद्योगपतियों पर कोई असर भी नहीं करता. आखिर पर्यावरण विभाग इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है कि उद्योग मनमानी करते रहें. उद्योगों की निगरानी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे कोई डर पैदा हो पाएगा? ■■

उपयोगिता

लघुकथा

पवन शर्मा

वह भीतर ही भीतर सुलग रहा है, कर कुछ भी नहीं पा रहा, करे भी तो क्या. ''क्या जरूरत है छुटकी को नौकरी करने की? क्यों?'' वह अपनी छोटी बहन को छुटकी ही कहा करता है, बचपन से.

''तुम तो हर बात पे क्यों लगा देते हो, कुछ समझते ही नहीं... अगर वह नौकरी कर रही है तो क्या बुराई है? रग्घू भी तो उसी के ऑफिस में काम कर रहा है. देखभाल तो करता ही होगा अपनी बहन की.'' वे चश्मे के भीतर से झांकते बोले.

''बाहर वाले बोलते हैं. कहते हैं- बेटी की कमाई घरवाले खाते हैं. ऐसी बातें मुझसे सहन नहीं होतीं. और फिर मैं कमा रहा हूं, रग्घू कमा रहा है, तब छुटकी को नौकरी करने की जरूरत ही क्या है?'' वह फिर कहता है, सुलगते हुए.

''तू अभी बच्चा है.''

''अगर तुमने छुटकी को नौकरी से नहीं हटवाया तो मैं उसे हटवा दूंगा... किसी भी तरह.'' वह फिर सुलग जाता है.

''...तो फिर रग्घू भी नौकरी से हट जाएगा, अपने आप ही. क्योंकि रग्घू की नौकरी छुटकी के कारण ही डेली बेसिस पर चल रही है... उसे कभी भी हटाया जा सकता है.'' वे सर्द आवाज में बोले.

सहसा उसे लगा जैसे शिराओं में खून जम-सा गया है. ■■

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

सत्ता में डबल रोल का खेल

हेमामालिनी, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों ने फिल्मों में डबल रोल करके बड़ी संख्या में दर्शकों को प्रभावित किया. संजीव कुमार ने तो एक फिल्म में सात से अधिक भूमिकाएं निभाकर लोगों को चौंकाया. हेमामालिनी, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, राज बब्बर जैसे अभिनेता फिल्म के साथ सत्ता की राजनीति में सक्रिय रहकर सामान्य जनजीवन में 'डबल रोल' करके सफल हो रहे हैं. रंगमंच पर एक ही दृश्य में डबल रोल करना संभव नहीं है, लेकिन राजनीतिक मंच पर 'मुखौटे' लगाकर डबल रोल के दृश्य अवश्य देखने को मिल रहे हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विस्थापित प्रचारक गोविंदाचार्य ने अपनी डायरी में कई वर्ष पहले अटलबिहारी वाजपेयी को भाजपा की सत्ता का 'मुखौटा' लिख दिया था. उस डायरी के पन्ने हाथ लगने पर मैंने अपने अखबार में उन पन्नों सहित एक बड़ी रिपोर्ट छाप दी तो हंगामा हो गया. 'मुखौटा' शब्द खूब चला लेकिन गोविंदाचार्य की भाजपा, संघ में 'घर वापसी' आज तक नहीं हो सकी. गोविंदाचार्य की मंडली मुझसे खफा रही. प्रामाणिक रिपोर्ट होने के कारण हमें कोई खंडन नहीं छापना पड़ा. लेकिन मेरे साथ बहुत से लोग यह अवश्य मान सकते हैं कि आखिरकार राजनीति में 'मुखौटे' का इस्तेमाल होता था और अब भी हो रहा है. फिर गोविंदाचार्य को दंडित क्यों किया गया? अटलजी की 'उदार छवि' का लाभ तो भाजपा ने हमेशा उठाया. 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड हो या 2002 में गुजरात के भयावह सांप्रदायिक दंगे की स्थिति रही हो, भाजपा ने उनको एक 'ऊंचाई' पर बैठाकर रखा तथा अपने सारे इरादे पूरे किए.

अब देखिए 'सत्ता की राजनीति' में मुखौटों का अद्भुत खेल जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की गंगा जैसी नदी राइन और फ्रांस की सीन नदी के किनारों पर सैर करते हुए वहां के नेताओं के सामने महात्मा गांधी के समरसतावाद, मानवतावाद, भारत की प्राचीन सभ्यता-संस्कृति के श्लोक सुना रहे हैं. जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा सहित दुनियाभर के देशों में बसे भारतीयों को शांति-सुख से रहने तथा समान लोकतांत्रिक अधिकार देने की उपयोगिता समझा रहे हैं. अगले महीने ब्रिटेन में बसे भारतीय पासपोर्ट धारक हजारों युवा-बुजुर्ग ब्रिटिश संसद के 7 मई को होनेवाले चुनाव में वोट डालने वाले हैं. लेकिन भारत में मोदी की अपनी सरकार की सहयोगी जर्मनी का इतिहास भारत में दोहरा सकता है. वैसे शराफत का चोगा पहनकर वह यह दावा कर रहे हैं कि वोट का अधिकार छीने जाने से उनका दुरुपयोग राजनीति में रुकेगा. इसी तरह प्रधानमंत्री राइन नदी की तरह भारत में गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जर्मनी के नेताओं ओर विशेषज्ञों से सहायता मांग रहे हैं और उसी शाम इधर उनकी ही भाजपा के भगवा वेशधारी सांसद आदित्यनाथ सरकार को सलाह दे रहे हैं कि हरिद्वार में गंगा किनारे 'हर की पौड़ी' पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए. आदित्यनाथ को उनकी सरकार के किसी सहयोगी ने यह नहीं बताया कि 'मोदी जी, परदेस से जिन विशेषज्ञों को बुला रहे हैं, वे धर्म से 'हिंदू' नहीं हुए हैं. कल्पना कीजिए,

अनेक अभिनेता फिल्म के साथ सत्ता की राजनीति में सक्रिय रहकर सामान्य जनजीवन में 'डबल रोल' करके सफल हो रहे हैं. रंगमंच पर एक ही दृश्य में डबल रोल करना संभव नहीं है, लेकिन राजनीतिक मंच पर 'मुखौटे' लगाकर डबल रोल के दृश्य अवश्य देखने को मिल रहे हैं.

शिवसेना के 'सूबेदार' सांसद संजय राऊत ने सलाह दी है कि भारत में ही पीढ़ियों से बसे 20 करोड़ से अधिक नागरिकों को अगले चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाए. मंत्रिमंडल में जल्द ही शिवसेना के दो-तीन सांसदों के जाने की तैयारी भी है. गनीमत है अभी शिवसेना ने महाराष्ट्र के पुराने समझौते की तरह राष्ट्रीय स्तर पर आधे कार्यकाल के बाद शिवसैनिक को प्रधानमंत्री बनाने का समझौता शायद नहीं कर रखा है. अन्यथा कोई 'आत्मघाती' दस्ता अध्यादेश लाकर वोट का अधिकार छीनकर जब भारत में विशाल गंगा किनारे जाने वालों को 'हिंदू' धर्म अपनाने का सरकारी 'आधार कार्ड' लेकर जाना पड़े. इसी तर्ज पर अमरनाथ, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले लोगों की सहायता में लगे मेहनती सहायकों (घोड़ा-पालकी संभालने वाले गैर हिंदू) को हटाने पर कितने यात्री वापस जीवित आ सकेंगे? आज गंगा पर प्रवेश का मुद्दा है. कल यमुना, नर्मदा, कावेरी, हिमालय, विंध्याचल में कदम रखने का मुद्दा उठे तो क्या होगा? वेश बदलकर या मुखौटे लगाकर सत्ता में आने वालों का मुंह बंद करने वाली कोई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देश में आएगी या नहीं?

भाजपा और उसको सत्ता में लाने का दावा करने वाली विश्व हिंदू परिषद तथा शिवसेना के कुछ नेताओं ने मोदीजी की यात्रा के दौरान एक सलाह यह भी दी थी कि अल्पसंख्यकों के लिए एक बच्चे के बाद नसबंदी अनिवार्य कर दी जाए. वहीं हिंदुओं को सलाह दी कि वे कम से कम चार या उससे अधिक बच्चे पैदा करें. आजकल पढ़ना-लिखना कम होने से उन्हें याद नहीं आया कि इंद्रप्रस्थ युग में महाराज धृतराष्ट्र की तो एक सौ संतानें थीं. उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि भाजपा और संघ के अनेक नेताओं ने तो विवाह ही नहीं किया. वे चार बच्चे पैदा करने के आदेश का पालन कैसे करेंगे? वे यह भी भूल गए कि 1975-77 की इमर्जेंसी और इंदिरा-संजय गांधी के सत्ता काल में बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान शुरू हुआ था और नसबंदी ऑपरेशन की ज्यादतियों का प्रचार कर रहे भारतीय जनसंघ के नेता जनता पार्टी के चुनाव अभियान में विजयी होकर सत्ता में पहुंचे थे. 'डिजिटल' सत्ता युग में नसबंदी की ज्यादतियों का प्रचार होने पर किसे फायदा मिलेगा? हाल के चुनाव से पहले अन्ना हजारे और फिर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी तथा अरविंद केजरीवाल के मुखौटे लगाए हजारों लोगों की रैलियां देखने को मिली थीं. इसलिए आजकल सरकारों और संगठन में सांसदों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों को पहचानना मुश्किल है. पता नहीं किस मुखौटे के पीछे कौन सामने मिल जाए.

ऐसा नहीं है कि 'मुखौटे' की राजनीति पर भाजपा का एकाधिकार है. कांग्रेस में भी झोला लटकाए अंग्रेजीदां जयराम रमेश या श्वेत वस्त्रधारी पी. चिदंबरम जैसे नेता गरीब किसान मजदूरों के लिए आंसू बहाते दिखते हैं और सत्ता की अपनी नीतियां उनके विरुद्ध बनाकर तांडव करते हैं. पुराने लोहियावादी जनता दल परिवार के कुछ बड़े नेता पारिवारिक विवाह समारोहों या जन्मदिनों पर टाटा-अंबानी के आयोजकों को मात करने वाली धन की चकाचौंध दिखाते हैं. हाथी-घोड़े ही नहीं, पचासों हवाई जहाजों से मेहमान बुलाकर पांच सितारा खातिरदारी नाच-गाना करते हैं. फिर 'मुखौटा' लगाकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर गरीबों के लिए संघर्ष की लाठिया घुमाते हैं. अरविंद केजरीवाल ने टोपी 'आम आदमी' की लगाई लेकिन सत्ता में खास होते ही कर्मठ साथियों को 'लात' मारकर निकालने की इच्छा जाहिर कर दी. वहीं रिकार्ड तोड़ संसदीय सचिव बनाकर खजाना खोल दिया. 'आम आदमी' धक्के खा रहा है. पुराने कामरेड्स की कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं का पतन 'अंग्रेजी' का मुखौटा पहनकर सत्ता का खेल करने के कारण ही हुआ. कुछ समय पहले मैंने एक बड़े प्रभावशाली नेता से आग्रह किया कि वह धर्मनिरपेक्ष और समाजमुखी लेख अंग्रेजी अखबारों की तरह हिंदी अखबारों-पत्रिकाओं को क्यों नहीं देते? उन्होंने बड़ी शालीन मधुरता से उत्तर दिया कि अंग्रेजी भाषा में पढ़ने वालों के लिए ये विचार पहुंचाना ज्यादा जरूरी है. मैं उनका सम्मान करता हूं और अपनी राय थोप नहीं सकता लेकिन इतनी असहमति व्यक्त करता हूं कि सामाजिक सौहार्द्र व जागरूकता के लिए हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में सद्विचारों का प्रसार अधिक जरूरी है. अन्यथा धर्म-जाति का मुखौटा लगाए लोग भोले भारतीयों को ठगते रहेंगे. ■■

ईरान पर हायतौबा, पाक को छूट?

रहीस सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

पिछले दिनों लुसाने (स्विट्जरलैंड) में 'पी-5+1' देशों (चीन, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी) ने लंबी कवायद के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते की रूपरेखा पर आंशिक सफलता अर्जित कर ली. माना जा रहा है कि अब ईरान अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमता में कमी लाएगा और बदले में उस पर लगे प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटा लिया जाएगा. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इसे 'ऐतिहासिक सहमति' मानते हैं, लेकिन यह सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं है. इस सहमति को उस स्थिति में ऐतिहासिक कहना गलत नहीं होगा जब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए 'लिटिल ब्वाय' और 'फैट मैन' की तुलना में आज के हाइड्रोजन बमों की क्षमता को देखने की कोशिश की जाएगी और हिरोशिमा के लगभग 90,000 से 1,66,000 के बीच तथा नागासाकी के 60,000 से 80,000 के आसपास लोगों का जीवन समाप्त होने संबंधी भयावह चित्र मस्तिष्क में निर्मित किया जाएगा. हालांकि इसके बावजूद कुछ अहम सवाल बाकी हैं, जिनके उत्तर तलाशना जरूरी है. पहला यह कि क्या इस सहमति के बाद एशिया में परमाणु खतरा पूरी तरह से समाप्त हो गया? दूसरा यह कि ईरानी परमाणु बम को 'पी-5+1' ने एशियाई शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों माना, जबकि पाकिस्तान जैसे देश कहीं अधिक खतरनाक हैं जिसे न केवल चीन बल्कि अमेरिका भी सहयोग दे रहा है? आखिर पाकिस्तान या चीन-पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम को दुनिया खतरे के रूप में क्यों नहीं देखती?

तमाम अध्ययन रिपोर्टें यह बताती हैं कि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा देश है जो सबसे तीव्र गति से अपना नाभिकीय शस्त्रागार विकसित कर रहा है. उसने हाल ही में इस दिशा में नए डेवलपमेंट किए हैं, वे भारतीय हितों के समक्ष आने वाले समय में चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं. यह वास्तव में चिंता का विषय है. यह चिंता तब और बढ़ जाती है कि चीन पाकिस्तान को अपना सबसे विश्वस्त साथी मानते हुए, उसे लगातार परमाणु हथियारों सहित अन्य कई प्रकार से ऐसी सहायता करे जिसका उद्देश्य भारत के विरुद्ध एक मोर्चा तैयार करना हो. ध्यान रहे कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने घोषणा की है कि उन्होंने 8 डीजल-इलेक्ट्रिक सबमेरीन खरीदने के लिए चीन के साथ एक नए करार को स्वीकृति दी है. न्यूक्लियर मिसाइलों से सुसज्जित इन सबमेरीन्स को पाकिस्तान चीन से 5 बिलियन डॉलर में खरीदेगा. महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका इन गतिविधियों को देखते हुए चीन-पाकिस्तान की साझा नाभिकीय रणनीति पर अंकुश नहीं लगाता बल्कि उसे सामरिक हथियारों की आपूर्ति भी करता है. उल्लेखनीय है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने 95 करोड़ 20 लाख

ईरानी परमाणु बम को 'पी-5+1' ने एशियाई शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों माना, जबकि पाकिस्तान जैसे देश कहीं अधिक खतरनाक हैं जिसे न केवल चीन बल्कि अमेरिका भी सहयोग दे रहा है?

डॉलर मूल्य के करार को मंजूरी दी है जिसके तहत पाकिस्तान को 15 एएच-1जेड जेट फाइटर, 1000 हेलफायर मिसाइलें और अन्य हथियारों की आपूर्ति की जाएगी. खास बात यह है कि अमेरिका दुनिया को यह भरोसा नहीं दिला पा रहा है कि उसके द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा. उसका तर्क यह है कि ऐसा करना अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुकूल है, इसलिए ऐसा कर रहा है. क्या इसे दक्षिण एशियाई शांति के अनुकूल माना जा सकता है?

पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में वृद्धि के साथ-साथ न्यूक्लियर वारहेड्स को ले जाने वाली मिसाइलों की संख्या में भी वृद्धि करता रहता है. अभी पिछले महीने ही उसने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था. यह मिसाइल भारत के किसी भी हिस्से तक नाभिकीय हथियारों को ले जाने में सक्षम है. भले ही भारत इस बात को स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यक्त न कर पाए लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार अपनी तैयारियों को पूरा करने की रणनीति पर कार्य कर रहा है और परमाणु हथियार व लांचिंग वेहिकल (मिसाइल) कार्यक्रम उसी का हिस्सा है. कुछ रक्षा विशेषज्ञ भी अपने अध्ययनों के जरिए इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि पाकिस्तान लगातार शार्ट रेंज टैक्टिकल वेपंस का निर्माण कर रहा है जिनका भारत के खिलाफ युद्ध में प्रयोग करना एकमात्र उद्देश्य है. पाकिस्तान के ये प्रयास पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत को शत्रु मानने के जुनून को दर्शाते हैं. इस राष्ट्र का यही जुनून पाकिस्तानी जनरलों को सरकार पर मजबूत नियंत्रण बनाए रखने की ताकत देता है. यही नहीं, यही कारण राष्ट्र के संसाधनों की मांग के लिए सेना को ताकत देता है और पाकिस्तान के सामाजिक-आर्थिक डायनामिक्स को विपरीत दिशा में ले जाता है.

अगर सिपरी (स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट) सहित कुछ अन्य रिपोर्टों पर नजर डालें तो पाकिस्तान के पास इस समय 120 नाभिकीय हथियार हैं और उनके इसी दशक में तीन गुना तक पहुंच जाने की आशंका है. हो सकता है कि पाकिस्तानी परमाणु हथियारों में हो रही तीव्र वृद्धि भारत को नाभिकीय हथियारों की होड़ के लिए उकसाए, जो अभी 100-110 के आसपास हथियार रखता है. लगभग 250 परमाणु हथियार रखने वाला और एशिया का सबसे आक्रमक देश, चीन पाकिस्तान के साथ तेजी से गठजोड़ बना रहा है. चीन इस समय पाकिस्तान के लिए सबसे अधिक सैन्य सामग्री आपूर्ति करने वाला देश है. वह पाकिस्तान को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और लड़ाकू विमान दे रहा है. वह पाकिस्तान में कम से कम दो परमाणु संयंत्रों का निर्माण कर रहा है.

यदि चीन-पाकिस्तान हिंद महासागर में अपनी मिसाइलें तैनात करने संबंधी योजना बना लें (वैसे चीन 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति का अंतिम लक्ष्य यही लगता है) और भारत भी अपनी सुरक्षा की चिंता करते हुए, ऐसा ही कदम उठाए तो केवल हिंद महासागर का ही मिजाज नहीं बिगड़ेगा बल्कि पूरे एशिया (विशेषकर दक्षिण एशिया) का मिजाज बिगड़ जाएगा, जिसे पुनः पुरानी स्थिति में ले जाना बेहद मुश्किल होगा. देखना है दुनिया चीन-पाक गठजोड़ को गंभीरता से लेगी या नहीं. ■■

दृढ़ता और सकारात्मक सोच से होते हैं करिश्मे

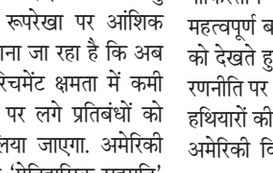

स्मार्ट स्ट्रीट बिजनेसमैन

प्रकाश बियाणी
कॉर्पोरेट इतिहासकार

दुनिया के कई देशों में हर वयस्क को एक निश्चित अवधि के लिए फौज ज्वाइन करनी पड़ती है. इसके पीछे सोच है कि फौजी ट्रेनिंग देशभक्त बनाती है. अनुशासन के साथ जीना सिखाती है. छह साल देश की वायु सेना में नौकरी करने के बाद अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की स्थापना करने और उसे देश की सबसे बड़ी हाउस होल्ड गुड्स मूवर्स कंपनी बना देने वाले रमेश अग्रवाल कहते हैं- दृढ़ता व सकारात्मक सोच से ही करिश्मे होते हैं.

6 सितंबर 1962 को नलवा (हिसार) हरियाणा में जन्मे रमेश अग्रवाल ने सरकारी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री लेने के बाद भारतीय वायुसीमा को एयरमैन की हैसियत से ज्वाइन किया. चेन्नई में वे 542 कैडेट्स में 'द बेस्ट एयरमैन' अवार्ड से नवाजे गए. छह साल देशसेवा करने के बाद 1987 में रमेश अग्रवाल ने घरेलू सामान के मूवमेंट के लिए एक कंपनी स्थापित की- अग्रवाल हाउस होल्ड कैरियर. उनकी सोच थी कि देश औद्योगिक प्रगति कर रहा है. लोग उन्नति के लिए बार-बार शहर बदलने लगे हैं. उनके लिए घरेलू सामान की पैकिंग व मूविंग आसान नहीं है.

रमेश अग्रवाल

घरेलू सामान की पैकिंग व मूविंग सेवा से शुरू हुआ छोटा-सा व्यवसाय तेजी से ग्रो हुआ. घरेलू सामान की सेफ पैकिंग व मूविंग सेवा को अच्छा रिस्पांस मिला. 1991 में देश की अर्थव्यवस्था ने करवट ली. मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां तीव्र हुईं. बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी भारत में एंट्री ली. भारत जैसे विशाल देश के दूरदराज के मार्केट तक गुड्स पहुंचाना उनके लिए चुनौती थी. अग्रवाल पैकर्स एवं मूवर्स ने कमर्शियल गुड्स की पैकिंग व मूवमेंट सेवा शुरू की तो कंपनी का नाम हो गया अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड. घरेलू सामान की तनावमुक्त शिफ्टिंग से रमेश अग्रवाल 'द मैन ऑफ लॉजिस्टिक्स' बने हैं. इसके लिए उन्होंने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स में ट्रांसपोर्ट वाहनों सहित पैकेजिंग मटेरियल सुविधाएं जुटाईं और कंपनी के कामकाज को कप्यूटराइज्ड किया. अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की वेयर हाउसिंग सेवाएं घरेलू व कारोबारी ग्राहकों ने खूब पसंद कीं. इसके लिए रमेश अग्रवाल ने ढाई लाख वर्गफुट के वेयर हाउसेस बनवाए हैं, जो बैंक लॉकर की तरह सुरक्षित हैं. देश के 14 राज्यों में 104 शाखाएं घरेलू व कारोबारी ग्राहकों को गुड्स पैकिंग व मूविंग सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं.

अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के रमेश अग्रवाल कई अवार्ड्स से नवाजे गए हैं, जिनमें उल्लेखनीय है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड (2010), स्टार ब्रांड्स इंडिया तथा सीएट आईआरटीए का पर्यावरण सुरक्षा अवार्ड. 650 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर करने वाली अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है. रमेश अग्रवाल तीन बार ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने तो वे इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन जिनेवा के भी सक्रिय सदस्य हैं. उनके द्वारा दुदु (राजस्थान) में स्थापित ड्राइवर सेवा केंद्र भी अपने किस्म की अनूठी पहल है.

सातों दिन 24 घंटे काम करने वाले रमेश अग्रवाल कहते हैं- मैं दिल से सोचता हूं, दिल से करता हूं और मेरे सहयोगी भी दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं. ग्राहक छोटा हो या बड़ा हम उसकी शिकायत की उपेक्षा नहीं करते क्योंकि इनका निराकरण करते हुए ही अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स व सप्लाय चेन कंपनी बनी है. कंपनी के अधिकांश कॉरपोरेट ग्राहक तो इतने सक्षम हैं कि वे अपनी खुद की लॉजिस्टिक कंपनी स्थापित कर लें, पर वे कहते हैं कि अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स कम लागत पर झंझटमुक्त सेवा प्रदान कर रहा है तो हम अतिरिक्त जवाबदारी का बोझ क्यों ढोएं. ■■

तोल बोल

संकट की इस घड़ी में मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं. मैं यह जानने उत्तर प्रदेश आया हूं कि किसानों का कितना नुकसान हुआ है.
■ राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री

मेरी तुलना सनी लियोनी के बजाय जेनिफर लोपेज और मैडोना जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से की जानी चाहिए.
■ राखी सावंत, अभिनेत्री

पाठकों के पत्र

कश्मीर में हिंसा

दो महीने की मशक्कत के बाद भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने अंततः अपनी पार्टी को सत्ता में भागीदार बनाकर पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद को जम्मू-कश्मीर का मुख्यमंत्री बनवा दिया. उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं. कश्मीर घाटी में हिंसक प्रदर्शनों तथा पथराव का दौर फिर शुरू हो गया. पाकिस्तान परस्त आतंकवादी मसर्रत आलम को मुफ्ती साहब ने सत्ता में आते ही रिहा कर दिया. उसने तुरंत भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. 15 अप्रैल को तो उसने श्रीनगर में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए तथा सैकड़ों लोगों के साथ उस देश का झंडा लहरा कर भारत की संप्रभुता को खुली चुनौती दी है. हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के प्रति भी मुफ्ती सरकार का रवैया बेहद ठंडा है. पहले उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनी बनाने की घोषणा की लेकिन दूसरे ही दिन अपने वादे से पलट गए. मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार जिस राह पर चल रही है, उससे कश्मीरी घाटी में अशांति ज्यादा बढ़ेगी. ■ धर्मदासी चावला, नागपुर

इतिहास पर नजर 19 अप्रैल

आज ही के दिन 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में एक सरकारी बिल्डिंग में हुए बम धमाके में 19 बच्चों समेत कुल 168 लोग मारे गए थे और 500 से ज्यादा घायल हुए थे. 9/11 हमले से पहले अमेरिका की धरती पर यह सबसे बड़ी आतंकवादी घटना थी. धमाका इतना भयानक था कि बचावकर्मियों को मलबे से शवों को निकालने में लगभग छह हफ्ते लग गए थे. ये धमाका एक कट्टरपंथी गुट डेविडियन पंथ के लोगों ने किया था. 1993 में टेक्सास शहर में डेविडियन पंथ के लोगों पर पुलिस कार्रवाई में 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे. इसी का बदला लेने के लिए इस पंथ के कुछ समर्थकों ने बम धमाका किया था. तीन लोगों को इसके लिए दोषी पाया गया था जिसमें एक को मौत की सजा दी गई जबकि दूसरे को उम्र कैद और तीसरे को 12 साल की सजा दी गई थी. ■■

- ■1451-बहलोल खान लोदी ने दिल्ली पर कब्जा किया.
- ■1775-अमेरिकी क्रांति की शुरुआत.
- ■1882-प्रसिद्ध जीवविज्ञानी चार्ल्स डार्विन का निधन.
- ■1910-हैली पुच्छल तारा पहली बार खुली आंखों से देखा गया.
- ■1948-च्यांग काई शेक चीन के राष्ट्रपति बने.
- ■1975-तत्कालीन सोवियत रूस की मदद से पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लांच किया गया.

gñWmnH$ gnmXH$: ñd. Odmhabmb XSm
M`a_Z, E{S>Q>m{a`b ~mS>© : {dO`XSm
E{S>Q>a-BZ-Mr\$: amOoÐ XSm
gnmXH : {dH$mg {_l★
★ nr. Ama. ~r. H$mZZ H$ AZgma gnU gnmXH$s` Xm{`Ëd H$ {bE {Oå_Xma.

© लोकमत समाचार _ àH$m{eV g^r gm_Jr H$m gdm©{YH$ma bmH$_V _r{S>`m àm`. {b. H$ nmg gm{j V h.
bmH$_V _r{S>`m àm`. {b. H$ {bE _ÐH$ Ed àHmeH बालाजी मुले Ûmam bmH$_V _r{S>`m àm.{b., ßbmQ> H$. 192, 207, 208 E_. AmB. S>r. gr. BÊS>{ñQ´>`b E[a`m, ~Qr~mar, ZmJna _ _{ÐV Ed bmH$_V ^dZ n. Odmhabmb Zhê$ _mJ, ZmJna _ àH$m{eV.
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
XaÜd{Z : 0712-2423527 (7 bmBÝg) \$Šg : 6618555
Email : gnmXH$s` : lsedit.ngp@lokmat.com
{dkmnZ : advt.ngp@lokmat.com {dVaU : circ.ngp@lokmat.com